


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2021 सैयदा मुनव्वर बनाम सईदुररहमान अन्तर्गत धारा 212 आरटीओए 1955</p>
<p>14.09.2021</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। विस्तृत आदेश प्रथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">   सहायक कलक्टर (मु०)  अजमेर </p>

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2021

1- सैययदा मुनवर पत्नी स्व0 अब्दुल राफे  
2- सैययद मोहम्मद नवेद पुत्र स्व0 अब्दुल राफे  
3- सैययद मोहम्मद जुनैद पुत्र स्व0 अब्दुल राफे  
समस्त जाति मुस्लमान निवासी 6/242 हबीब मंजिल, खादिम मौहल्ला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

- 1- सईदुररहमान पुत्र स्व0 अब्दुल नाफे जाति मुसलमान निवासी जरिये एस.एम.यासिर रहमान, बी. ब्लॉक, 8/8 सराय खलील, ईदगाह रोड, दिल्ली- 110006 (6/242, हबीब मंजिल, चाह अरहत मस्जिद के पास, खादिम मौहल्ला, अजमेर-305001)  
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अजमेर जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम 1955

समक्ष

श्रीमति तारामति वैष्णव आर0ए0एस

उपस्थित:-

- |    |                       |                            |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 1- | श्री अभिषेक शर्मा     | अभिभाषक प्रार्थी           |
| 2- | श्री आशीष जैन         | अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 |
| 3- | श्री ओम प्रकाश गुर्जर | राजकीय अभिभाषक             |

आदेश

दिनांक 14.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिसके साबिक खसरा संख्या 798 रकबा 27-03-00 है जिसके नये खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41 हैक्टयर कायम किये गये हैं उक्त भूमि के पश्चिमी ओर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 797 रकबा 20-11-10 स्थित है जिसके नये खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टयर तथा 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टयर कायम किये गये हैं। उक्त भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे बटवारे के उपरान्त उनके हिस्से में आई भूमि के अनुसार बतौर खातेदार काश्त करते रहे हैं स्व0श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 798 पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई अन्य हिस्सा व अधिकार इस भूमि में नहीं है ना ही प्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, बय, मुन्तकिल की गई है ना ही उक्त भूमि का कब्जा आज तक किसी अन्य व्यक्ति के पास रहा है। वर्षों से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं, परन्तु साबिक नक्शा वर्ष 1970 से 1971 के उपरान्त बने नये नक्शा वर्ष 1983 से 1984 में बदलाव हो जाने के कारण हाल प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान मू0राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका जो न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु नये नक्शे में हुई त्रुटि का अनुचित फायदा उठाने की मंशा से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की नियत से भूमि पर दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने लगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से मौखिक निवेदन किया कि आप हमारे खातेदारी की भूमि में कब्जा नहीं करे ना ही



कसी प्रकार हमारी खातेदारी की भूमि में दखलान्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान ने साफ तौर पर कह दिया कि तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है तुम्हारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है तुम यंहा से भांग जाओ। जिस पर प्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के यंहा नक्शा दुरुस्तगी का प्रकरण विचाराधीन है जो न्यायालय तय करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन उसने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी जमीन ज्यादा है तुम्हारी कम है ओर नये नक्शे के अनुसार हम तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेगे ओर अप्रार्थी संख्या 1 की जमीन में मिलाकर बैचान कर देगे। प्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से निवेदन किया कि आप हमारी जमीन पर अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देशानुसार कब्जा नहीं करेगे तो भी अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदार लडाई-झगडा करने पर उतारू हो गये एंव प्रार्थी संख्या 2 व 3 को धमकी दी की तुम यंहा से चले जाओ अन्यथा हम तुम्हे मार पीट कर मगा देगे मौके पर इगडे की स्थिति को दखते हुए प्रार्थी संख्या 2 व 3 अपनी जान बचाकर भाग आये। अप्रार्थी संख्या 1 के रिश्तेदार व नौकर के साथ अन्य लोग भी डंडे व लाठी लिये हुए खडे थे तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 को मारने एंव लडाई झगडा करने पर आमादा थे प्रार्थी संख्या 1 बेवा वृद्ध महिला है जिसकी जमीन हडपने की नियत से समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी मार्च 2021 में अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र तथा रिश्तेदारान के संग मौके पर आ गये तथा प्रार्थीगण के पूर्वज के मना करने पर भी प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने लगा एंव मना करने पर भी प्रार्थीगण के पूर्वज स्व०अब्दुल राफे से भी लडाई-झगडा करने पर आमादा हो गये, उसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देश पर अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त उसके रिश्तेदार व नौकर मौके पर आकर गलत नक्शे का हवाला देते हुए प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे जिस पर प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के द्वारा उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ लडाई झगडा नहीं करे न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है उसमें जो निर्णय होगा वह हमे मान्य होगा, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदार ने कहा की अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि बैचनी है ओर वे भूमि नये नक्शे के अनुसार ही बैचान करेगे, अगर उसने तुम्हारी भूमि कम होती है तो उसमें हमे कुछ लेना देना नहीं है हम तुम्हारी भूमि को भी अपनी भूमि में मिलाकर बैचान कर देगे तथा तुम्हे बेदखल करेगे। अन्त में प्रार्थीगण के विद्वान अभिनाथक ने निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि खसरा संख्या 798 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भूमि का मन चाहा उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है। यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा, वयोकि प्रार्थीगण उक्त भूमि में उनके पूर्वज स्व०श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त बतौर मालिक स्वामी काबिज काश्त चले आ रहे है। यदि अप्रार्थी द्वारा भूमि का बैचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अभिनाथक ने 16.07.2021 को अपना जवाब मय वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन कि प्रार्थीगण को



अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अभिनाथक ने 16.07.2021 को अपना जवाब मय वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन कि प्रार्थीगण को

प्रस्तुत प्रकरण मे सफलता मिलना व्यर्थ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध मे तथ्य स्वयं साबित करे। चरण संख्या 3 से 10 गलत होने से अस्वीकार किया गया है तथा बिन्दु संख्या 10 व 11 न्यायालय से सम्बन्धित होने का उल्लेख अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जवाब मे अंकित अतिरिक्त कथन अंकित कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 रा0मू0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की स्ट्रेज का अनुतोष नहीं मिला है तथा यंहा प्रार्थी असफल होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार से हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी एक तरफ तो उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष धारा 131 मू0रा0अधि0 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वही दूसरी ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे वाद कारण नक्शे मे त्रुटि होना अंकित किया गया है। मननीय न्यायालय ने इस बात पर गोर नहीं किया कि प्रार्थी द्वारा जो वाद मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो क्लीन हेण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आने के कारण चलने योग्य नहीं है लिहाजा दिया गया उक्त प्रार्थना पत्र गलत होकर काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे जिस आराजी का उल्लेख अंकित किया गया है उसके खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टर व खसरा नम्बर 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टर दोनो खसरा नम्बरान अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है इस कारण एक खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से न्यायालय के द्वारा पाबन्द नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास पूर्ण किया है प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया गया है। नक्शे मे परिवर्तन का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 88, 188 मे अंकित नहीं किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी सूरत मे चलने योग्य नहीं है जिस नक्शे को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वे नक्शा सन 1983-84 का होना दर्शाया गया है उक्त प्रकरण 37-38 वर्षो के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रार्थीगण के द्वारा कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है उक्त कारण से दिया गया अन्तरिम आदेश गलत है। प्रार्थी द्वारा नक्शे मे परिवर्तन के आधार पर दखलन्दाजी के बाबत धारा 131 मू0रा0अधि0 प्रार्थना पत्र तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमे उनके द्वारा किसी भी भूमि की सीमाओ के बारे मे उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। मात्र कल्पनाओ के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। धारा 131 मू0रा0अधि0 के आवेदन पत्र का प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी तरह की देरी करने की मंशा हमारी नहीं रही है प्रार्थी द्वारा इन तथ्यो की जानकारी छुपाने के बावजूद प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य गलत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी की उम्र लगभग 75 वर्ष है जो कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व वाद मे वाद कारण अंकित किया गया है। उस दिवस को अप्रार्थी अजमेर मे नहीं होकर अजमेर से बाहर गये हुए थे, परन्तु मनगढन्त कहानी के आधार पर प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति मे चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र पर मे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष कतई प्रतीत नहीं होता है। अन्त मे प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन



किया। अप्रार्थी के अभिभाषक के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी अभिभाषक के द्वारा अपने तत्वों एवं बहस के समर्थन में 2013 आर0आर0टी0(1) पेज 123, 183, 2016 आर0आर0टी0पार्ट (2) पेज 1823, 2016 आर0जी0जे0 पेज 245, 2012 आर0बी0जे0 05, 2016 आर0बी0जे0 पेज 144, 1985 आर0आर0डी0 पेज 30 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण खातेदारी की भूमि से सम्बन्धित है जिसमें राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है, उनके निवेदन अनुसार राजस्थान सरकार का जवाब दिनांक 31.08.2021 को बन्द किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक ने स्वयं निवेदन किया कि राजस्थान सरकार के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा उदघोषणा के बाद में भूमिधारी होने के कारण पक्षकार मुर्तिब किया गया है।

उक्त जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण के द्वारा दिनांक 31.8.2021 को प्रकरण में अन्तिम बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उमय पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी जिसके साबिक खसरा संख्या 798 रकबा 27-03-00 है जिसके नये खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41 हैक्टर कायम किये गये है उक्त भूमि के परिचामी ओर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 797 रकबा 20-11-10 स्थित है जिसके नये खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टर तथा 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टर कायम किये गये है उक्त भूमि का उपयोग उपमोग प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे बटवारे के उपरान्त उनके हिस्से में आई भूमि के अनुसार बतौर खातेदार काशतकार करते आ रहे है तथा स्व0श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 798 पर बतौर खातेदार काशतकार काबिज काशत है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई अन्य हिस्सा व अधिकार नहीं है ना ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, बय, मुन्तकिल ही की गई है ना ही उक्त भूमि का कब्जा आज तक किसी नये व्यक्ति के पास रहा है। वर्षों से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक भूमि का उपयोग व उपमोग करते आ रहे है। परन्तु साबिक नवशा वर्ष 1970 से 1971 के उपरान्त बने नये नवशे वर्ष 1983 से 1984 में बदलाव हो जाने के कारण हाल प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उक्त प्रकरण विचाराधीन है परन्तु नये नवशे में हुई त्रुटि का अनुचित फायदा उठाने की मंशा से वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि पर कब्जा करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर चाकर व उनके जानकार रिश्तेदार प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काशत भूमि पर दखलन्दाजी व मदाखलत करने लगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान से मौखिक निवेदन किया कि आप हमारे खातेदारी की भूमि में कब्जा नहीं करे ना ही किसी प्रकार हमारी खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे। अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान ने साफ तोर पर कह दिया कि तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है तुम्हारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है तुम यहा से मांग जाओ। जिस पर प्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदारान ने कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर के यहा नवशा दुरुस्तगी का प्रकरण विचाराधीन है जो न्यायालय तय करेगा उसको हम



अजमेर के यहा नवशा दुरुस्तगी का प्रकरण विचाराधीन है जो न्यायालय तय करेगा उसको हम

मानेंगे। परन्तु उसने साफ तोर पर कह दिया कि हमारी जमीन ज्यादा है तुम्हारी कम है और नये नक्शे के अनुसार हम तो जमीन पर कब्जा करेंगे तथा अप्रार्थी संख्या 1 की जमीन से मिलाकर बैचान कर देंगे। प्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 नौकर व रिश्तेदारान से निवेदन किया कि आप हमारी जमीन पर अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देशानुसार कब्जा नहीं करेंगे तो भी अप्रार्थी संख्या 1 नौकर व रिश्तेदार लडाई-झगडा करने पर उतारु हो गये तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 को घमकी दी की तुम यंहा से चले जाओ अन्यथा हम तुम को मार पीट कर मगा देगे मौके पर झगडे की स्थिति को देखते हुए प्रार्थी संख्या 2 व 3 अपनी जान बचाकर भाग आये। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के रिश्तेदार व नौकर के साथ अन्य लोग भी डंडे व लाठी लिये हुए खडे थे तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 को मारने तथा लडाई झगडा करने पर आमादा थे, प्रार्थी संख्या 1 बेवा वृद्ध महिला है जिसकी जमीन हडपने की नियत से समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा की जा रही है। पूर्व मे भी मार्च 2021 मे अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र तथा रिश्तेदारान के संग मौके पर आ गये तथा प्रार्थीगण के पूर्वज के मना करने पर भी प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने लगा एंव मना करने पर भी प्रार्थीगण के पूर्वज स्व0अब्दुल राफे से भी लडाई-झगडा करने पर आमादा हो गये, उसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 के निर्देश पर अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त उसके रिश्तेदार व नौकर मौके पर आकर गलत नक्शे का हवाला देते हुए प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे जिस पर प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के द्वारा उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ लडाई झगडा नहीं करे न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है उसमे जो निर्णय होगा वह हमे मान्य होगा, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के नौकर व रिश्तेदार ने कंहा की अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि बैचनी है और वे भूमि नये नक्शे के अनुसार ही बैचान करेंगे। अगर उसमे तुम्हारी भूमि कम होती है तो उसमे हमे कुछ लेना देना नहीं है हम तुम्हारी भूमि को भी अपनी भूमि से मिलाकर बैचान कर देगे तथा तुम्हे बेदखल करेंगे। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है क्योंकि खसरा संख्या 798 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भूमि का मन चाहा उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र है। यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा, क्योंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि मे उनके पूर्वज स्व0श्री अब्दुल राफे की मृत्यु के उपरान्त बतौर मालिक स्वामी काबिज काश्त चले आ रहे है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे किया जाना संभव नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा अपने कथनो के समर्थन मे 2019 आरबीजे पेज 129, 551, 2020 आरबीजे पेज 82,726, नजीरे प्रस्तुत की गई।

जवाब मे अप्रार्थी संख्या 1 के विद्धान अभिभाषक के द्वारा जवाब मे अंकित तथ्यो एंव अतिरिक्त कथन मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 रा0मू0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार की स्ट्रेज का अनुतोष नहीं मिला है तथा यंहा प्रार्थी असफल होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमे प्रार्थी को किसी भी प्रकार से हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा एक तरफ तो उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष धारा 131 मू0रा0अधि0 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया दूसरी ओर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया



सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर

असमें वाद कारण नक्शे में जुट्टि होना अंकित किया गया है। माननीय न्यायालय में इस बात पर धोर नहीं किया कि प्रार्थी द्वारा जो वाद मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो क्लीन हेन्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आने के कारण चलने योग्य नहीं है लिहाजा दिया गया उक्त प्रार्थना पत्र गत होकर काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिस आराजी का उल्लेख अंकित किया गया है उसके खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टर व खसरा नम्बर 1161/1889 रकबा 0.50 हैक्टर दोनो खसरा नम्बरान अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे कास्ट की भूमि है इस कारण एक रिकार्ड खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से न्यायालय के द्वारा पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा मात्र नक्शे के आधार पर वाद कारण अंकित किया गया है उसके लिए पहले तो प्रार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में धारा 131 रू0भूरा0अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रकरण परीक्षण न्यायालय में विचारधीन है दूसरी ओर राजस्थान कास्टकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत जो अनुतोष चाहा गया है उसमें भी उक्त वाद कारण नक्शे में परिवर्तन के आधार पर होना बताया गया है जो कि सरासर गलत है लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को गुनराह करने कर का पूर्ण प्रयास किया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय वाद स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया गया है। नक्शे में परिवर्तन का सैत्राधिकार अधिनियम की धारा 88, 188 में अंकित नहीं किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी सूत्र में चलने योग्य नहीं है जिस नक्शे को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वे नक्शा सन 1983-84 का होना दर्शाया गया है उक्त प्रकरण 37-38 वर्ष के बाद नियाम बाहर प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रार्थीगण के द्वारा कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया गया है उक्त कारण से दिया गया अन्तरिम आदेश गलत है। प्रार्थीगण द्वारा नक्शे में परिवर्तन के आधार पर दखलन्दाजी के बाबत धारा 131 भूरा0अधि0 प्रार्थना पत्र तथा राजस्थान कास्टकारी अधिनियम के तहत उक्त दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा किसी भी भूमि की सीमाओं के बारे में उल्लेख अंकित नहीं किया गया है। मात्र कल्पनाओं के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। धारा 131 भूरा0अधि0 के आवेदन पत्र का प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी तरह की देरी करने की मंशा हमारी नहीं रही है प्रार्थी द्वारा इन तथ्यों की जानकारी छुपाने के बावजूद प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुनराह किया गया है लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी की उम्र लगभग 75 वर्ष है जो कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति है प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व वाद में वाद कारण अंकित किया गया है। उस दिवस को अप्रार्थी अजमेर में नहीं होकर अजमेर से बाहर गये हुए थे, जिससे मनगढन्त कहानी के आधार पर प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र तीनों घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णता क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है, अन्त में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने पुरजोर विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया।

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को निम्नांकित तीन आवश्यक बिन्दुओं पर विनिरिचय किया जाना है-

1-प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन

2-कब्जा

अजमेर कलेक्टर (3) अजमेर



### 3-अपूर्तनीय क्षति

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण तथा सुविधा का सन्तुलन :-

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार जमाबन्दी संवत् 2041 में खसरा संख्या 797 रकबा 20-11-00 बीघा अप्राथी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। जिसके प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित तथ्यों के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 1161 रकबा 2.83 हैक्टर तथा 1161/1869 रकबा 0.50 हैक्टर कायम किया जाना अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि साबिक एवं हाल रकबे में कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार वर्किंग खसरा संख्या 798 रकबा 27-03-00 प्रार्थीगण के पूर्वज अब्दुल राफे की खातेदारी में दर्ज है जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41 हैक्टर बनाये गये हैं। जो हाल जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है तथा साबिक एवं हाल रकबा में कोई अन्तर दर्शित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वर्किंग जमाबन्दी एवं आधार जमाबन्दी में दोनों पक्षकारान के नाम खातेदारी एवं रकबे में कोई अन्तर नहीं है। जिससे दोनों पक्षकारान अपने अपने नाम दर्ज खातेदारी की भूमियो पर जमाबन्दी में दर्ज रकबो के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। लेकिन पत्रावली पर प्रस्तुत साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस में विराघामास दृष्टिगोचर होता है। प्रार्थीगण की भूमि साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले हाल नक्शा ट्रेस में कम रकबा दर्शित होना स्पष्ट है वही अप्राथी की भूमि साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले हाल नक्शा ट्रेस में बेशी रकबा दर्शित होता है। उभय पक्षकारान के मध्य उक्त वाद का मूल कारण बन्दोबस्त विभाग के द्वारा साबिक नक्शों के मुकाबले हाल नक्शों में किया गया परिवर्तन ही प्रतीत होता है जबकि साबिक एवं हाल जमाबन्दी में रकबा यथावत दर्ज है। लेकिन अप्राथी के नाम दर्ज भूमि नक्शा ट्रेस हाल में बेशी दर्शा देने के कारण ही अप्राथी द्वारा उक्त अधिक दर्शित रकबे को अवैधानिक रूप से प्राप्त करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष नक्शा दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भूरा0अधि0 एवं मौके पर जमाबन्दी में दर्ज रकबे को विधिक रूप से सुरक्षित करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल नक्शा ट्रेस में कारित त्रुटि के कारण किसी पक्षकार का अहित होता है तो उसके काश्तकारी स्वत्वों की रक्षा किया जाना न्यायोचित है जिससे प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहित करता है।

2- कब्जा :-

पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में उभय पक्षों के द्वारा अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण जमाबन्दी में दर्ज रकबो के अनुसार अपनी अपनी खातेदारी की भूमियो पर काबिज काश्त होना स्वीकार किया गया है एवं बन्दोबस्त से पूर्व एवं उपरान्त की जमाबन्दियो में दोनों पक्षकारान की खातेदारी में दर्ज भूमियो के रकबे में कोई अन्तर नहीं है। जिससे उभय पक्षकारान जमाबन्दी में दर्ज रकबो के अनुसार ही काबिज होना प्रतीत होता है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में अप्राथी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि का रकबा बेशी दर्शित किया प्रतीत होता है लेकिन कब्जा काश्त उक्त बेशी रकबे पर सिद्ध नहीं किया गया है बल्कि जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार ही काबिज प्रतीत होते हैं।

3- अपूर्तनीय क्षति:-

बन्दोबस्त विभाग के द्वारा वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के पूर्वज एवं अप्राथी संख्या 1 के नाम दर्ज रकबे में साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले बदलाव किया जाना प्रार्थीगण द्वारा अंकित किया गया है एवं प्रार्थीगण के द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उक्त बदलाव के कारण अप्राथी



25/10/2023 कलक्टर (3) अजमेर

संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगण की भूमि को सम्मिलित करते हुए बैचान करने पर आगदा है ऐसी स्थिति में यदि बन्दोबस्त विभाग के द्वारा वर्तमान नक्शा ट्रेस में किये गये परिवर्तन के कारण यदि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न की जाती है तथा रहन बैचान मुत्तकिल किया जाता है तो प्रार्थीगण को क्षति कारित होना स्पष्ट है। जिससे अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निहित करता है।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोन किया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है ग्राम गेगल स्थित भूमि साबिक खसरा संख्या 798 रकबा 27-03-00 है जिसके नये खसरा संख्या 1160 रकबा 4.41 हैक्टर कायम किये गये हैं पर उभय पक्ष को वर्तमान मौके एवं कब्जे की यथास्थिति बनाए रखने हुत ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। आदेश आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर  
मुख्य कलेक्टर (पु), अजमेर  
(मुख्यालय) अजमेर

